एक आइकन का अवसान

विकास नारायण राय

किरण बेदी ने अपनी आत्मकथा आइ डेयर को एक खुली किताब कहा है। लगता हैए अब यह किताब बंद की जा रही है। या इसमें एक चमकते हुए आइकन के अस्त होने का अध्याय दर्ज करने की तैयारी है भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम महिला अफ्सर किरण बेदी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं इस गरमाती बहस के बीच उनकी आइकॉनिक छवि का अवसान निश्चित ही एक संभावना है। अचानकए दिल्ली चुनाव में राजनीतिक समझौतेबाजी की चुनावी बिसात पर खुल कर उतरने से उनकी खरी चमक का धुंधलाना स्वाभाविक है।

एक पुलिस अफ्सर के रूप में बेदी की पेशेवर साख चाहे कुछ खास न रही हो, पर निर्विवाद है कि आजादी के पचीस वर्ष बाद भारतीय पुलिस सेवा में जिद के साथ प्रवेश करने वाली यह महिला हजारों भारतीय महिलाओं के लिए खाकी वर्दी धारण करने की प्रेरणा का स्रोत बनी। घोर पितृसत्तात्मक भारतीय समाज के लिए वरिष्ठ पुलिस अफ्सर के वेश में किरण बेदी को अपराध नियंत्रण जैसे पारंपरिक मर्दाने क्षेत्र में सैकड़ों पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करते हुए देखनाए, स्त्री की कमजोर फ्तिरत का सामाजिक तिलिस्म दरकने जैसा अनुभव रहा होगा। लेकिन आज समाज के सामने अलग ही तस्वीर आ रही है, इस आइकन के एक आरोपित चुनावबाज के बिंब में कायांतरण की!

जाहिर है कि अगर भाजपा नेतृत्व ने दिल्ली में बेदी को पार्टी पर थोपने की सोची.समझी कवायद की है तो यह घटनाक्रम बेदी के उनके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के बिना संभव नहीं हो सकता था। इसके बीच यह पाखंड गले से उतारना मुश्किल हो जाता है कि बेदी एकाएक प्रधानमंत्री मोदी के किसी सबका विकास एजेंडे से प्रभावित होकर राष्ट्रसेवा करने राजनीति में उतरी हैं। क्योंकि आज तक तो देशवासियों के सामने मोदी शासन का कॉरपोरेट हितों के पोषण का इकतरफ एजेंडा ही सामने आया है। दूसरी तरफए जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी संकीर्ण हिंदुत्ववादी भाव.भंगिमा में रत्ती भर दिखावटी फेरबदल नहीं किया हैए उसे भी बेदी ने एक ही सांस में राष्ट्रीय एकता का पहरेदार घोषित कर दिया। यह महज अवसरवादिता नहींए आत्मसमर्पण है।

अण्णा के लोकपाल मंच की आभा से आलोकित बेदी के लिए भाजपाई सहयोगियों के भ्रष्टाचार पर तो बगलें झांकने के सिवा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। इस समर्पण क्रम में उनका चालीस सालों के प्रशासनिक अनुभव का दावा भी एक निहायत खोखला तर्क लगता है। अपने लंबे सेवाकाल मेंए उन्हें पुलिस विभाग में

एक पुलिस अफ्सर के रूप में बेदी की पेशेवर साख चाहे कुछ खास न रही हो, पर निर्विवाद है कि आजादी के पचीस वर्ष बाद भारतीय पुलिस सेवा में जिद के साथ प्रवेश करने वाली यह महिला हजारों भारतीय महिलाओं के लिए खाकी वर्दी धारण करने की प्रेरणा का स्रोत बनी। घोर पितृसत्तात्मक भारतीय समाज के लिए वरिष्ठ पुलिस अफ्सर के वेश में किरण बेदी को अपराध नियंत्रण जैसे पारंपरिक मर्दाने क्षेत्र में सैकड़ों पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करते हुए देखना, स्त्री की कमजोर फ्तिरत का सामाजिक तिलिस्म दरकने जैसा अनुभव रहा होगा। लेकिन आज समाज के सामने अलग ही तस्वीर आ रही है, इस आइकन के एक आरोपित चुनावबाज के बिंब में कायांतरण की!

व्यास भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर किसी पहल के लिए नहीं जाना जाता। न ही भ्रष्ट पुलिस प्रणाली से समाज को राहत दिलाने वाले किसी बुनियादी बदलाव को चिह्नित करने के लिए ही। आश्चर्य नहीं कि भाजपा में प्रवेश के साथ वे संसद में सरकारी नौकरशाही पर केंद्रित लोकपाल बिल पारित होने मात्र को इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान का सफल समापन कहते नहीं थक रहीं। राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट पूंजी के भ्रष्ट याराने पर उनकी चुप्पी मोदी और जेटली की आर्थिक प्राथमिकताओं को ही तो ध्वनित करती हैए न कि आम जन के पक्ष में आइ डेयर को। महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों के मोर्चों पर भी किरण बेदी की सफलता के दावे प्रशासनिक आंकड़ा पद्धति के अनुरूप हैंए न कि जन.कसौटी के धरातल पर। स्त्री विरुद्ध अपराधों को कम दर्ज करके पुलिस बेहतर महिला सुरक्षा का खोखला दावा पेश करती आई है। वर्ष 2014 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने जैसे ही मुक्त रूप से मुकदमे दर्ज करने की सही रणनीति अपनाईए इन अपराधों में अभूतपूर्व वृद्धि तुरंत सामने आ गई।

दिल्ली पुलिस की वार्षिक मीडिया प्रस्तुति में बस्सी ने इनकार नहीं किया कि जमाने से इन अपराधों का आंकड़ा प्रबंधन ही किया जा रहा था। क्या यह सवाल नहीं बनेगा कि किसी किरण बेदी का इस ष्प्रबंधनष् के समांतर या विरोध स्वरूप अपना ट्रैक रिकार्ड क्या रहा है।

इसी तरह नारकोटिक्स ब्यूरो में तैनाती के दौरान मादक पदार्थों की बरामदगी के मात्र बढ़े.चढ़े आंकड़े किरण बेदी की पीठ थपथपाने के लिए काफी नहीं माने जा सकतेए जबकि समाज में इनकी आपूर्ति का चक्र निर्विघ्न चलता रहा हो। ब्यूरो में उनसे बेहतर आकड़े दिखाने वाले भी रहे हैं और कौन नहीं जानता कि आंकड़ों का खेल तमाम सरकारी प्रवर्तन एजेंसियां कैसे खेलती आई हैं।

पंजाब के संदर्भ मेंए जहां भाजपा के सहयोग से राज करने वाले अकाली दल का मुखिया परिवार ही इस चक्र को लेकर संदेह के बादलों से भरा है, क्या इस विषय में पूछताछ करने वाले अफ्सर के तबादले को लेकर आज आइ डेयर करने की हिम्मत बेदी में है यह बेमौसम तबादला मोदी के खास जेटली के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किया।

बेदी का महिला सुरक्षा का ब्लू प्रिंटए जिसे उनके लेखन में देखा जा सकता है, पारंपरिक राजनेताओं के तौर.तरीकों से हट करए आधुनिक संदर्भों में महिला सशक्तीकरण की चुनौती के सवाल जरूर उठाता है। लेकिन उनके बताए कानूनी या प्रशासनिक हल भी नौकरशाही और योजनाकारों के जाने.पहचाने ढर्रे के माफ्िक ही हैंए जिनसे राज्य अपनी पीठ बेशक थपथपा लेए स्त्री फ्िर भी असुरक्षित रह जाती है। बेदी के नवीनतम नायक मोदी ने इसी बाईस जनवरी को पानीपत में महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय कार्य.योजना ष्बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में समेट कर रख दी। इस अवसर पर मोदी की बड़ी चिंता थी कि अगर कन्या भ्रूण हत्या चलती रही तो विवाह के लिए लड़कियां कहां से आएंगी। उनकी एक मंत्री का रोना था कि बेटी न होने से वे कन्यादान का पुण्य नहीं उठा पा रही हैं। यह महिला सशक्तीकरण का सोच हुआ या उसे व्यक्तित्वविहीन रखने काघ् भाजपा और मोदी की कृपा से मुख्यमंत्रित्व पाने के बाद क्या बेदी इस सोच के मुकाबले आइ डेयर कर सकती हैंद्ध

सही है कि दिल्ली चुनाव की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बेदी को जांचने.परखने का पैमाना असाधारण रूप से कसा रखा जा रहा है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि चुनावी रंगमंच पर उनका प्रवेश असाधारण तौर पर हुआ, बल्कि एक तरह से यह उनके आइकॉनिक व्यक्तित्व की नियति भी रही है। बंदिशों से भरे पुलिस विभाग के वरिष्ठों और समकक्षों से भी उनका रिश्ता बहुत सहज नहीं कहा जा सकता।

दरअसलए चालीस वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के दावों के बावजूदए कड़वी सच्चाई यह भी है कि केंद्र सरकार में वे एडिशनल डीजी पद की पात्रता के लिए भी उपयुक्त नहीं ठहराई गईं हालांकि बाद में शीर्ष राजनीतिक दखल के चलते गृह मंत्रालय को उनके नाम को एडिशनल डीजी और डीजी पदों की चयनित सूची में जगह देनी पड़ी। भारत सरकार ने उन्हें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे महत्त्वपूर्ण संगठन का मुखिया भी बनाया। तो भी, प्रचार से कटे रह कर काम करने की यह भूमिका उन्हें रास नहीं आई और अंततरू दिल्ली का पुलिस कमिश्नर न बनाए जाने पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। समयपूर्व इस्तीफे को बेदी कैंप काफी महिमामंडित कर रहा है। जबकि इसमें सिद्धांतों के लिए त्याग जैसा कुछ भी नहीं था। वे उस समय केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर होती थीं। इसलिए दिल्ली पुलिस में पूर्ण पात्रता वाले उनसे कनिष्ठ अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाना न प्रशासनिक रूप से अप्रत्याशित कहा जा सकता है और न नियम विरुद्ध।

इससे पहले और इसके बाद भी सारे देश में ऐसे ही पचासों मामले देखे जा सकते हैं। बल्कि तमाम ऐसे भी उदाहरण हैंए जहां कैडर में ही कार्यरत वरिष्ठ को पुलिस प्रमुख न बना कर अन्य समकक्ष पद पर लगाया गया। यहां तक कि कितने ही मामलों में तो योग्यतम अधिकारियों की भी राजनीतिक कारणों से अनदेखी की गई।

बेदी को अगर वास्तव में सैद्धांतिक विरोध करना थाए तो उन्हें इन मामलों में भी आवाज उठानी चाहिए थी या कम से कम इस्तीफा देते समय इनका भी हवाला देना चाहिए था। उस समय तक प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का पुलिस सुधार को लेकर फैसला भी आ चुका थाए जिसके अनुसार सरकार कैडर के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से पुलिस प्रमुख चुन सकती थी। बेदी का मामला इस मानदंड के अनुसार ही तय हुआ था।

यह जानना दिलचस्प होगा कि बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री खुद मोदी का वरिष्ठता और योग्यता को लेकर अपना रवैया क्या रहाघ् उस दौर में गुजरात में लगभग तीन वर्ष तक राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर नियमित तैनाती ही नहीं की गई, क्योंकि वरिष्ठतम योग्य अफ्सर मोदी के माफ्िक नहीं बैठता था।

तब बेदी सरकारी सेवा में भी नहीं थीं और आसानी से इस घोर अनियमितता के विरुद्ध आवाज उठा सकती थीं। बशर्ते अपने इस्तीफा प्रकरण में उनका विरोध किन्ही सिद्धांतों पर आधारित रहा होता। सच्चाई यह है कि उन्होंने तब भी व्यक्तिगत महात्त्वाकांक्षा को ही सर्वोपरि रखा।

यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि किरण बेदी के व्यक्तित्व से पुलिस महकमे की बदनाम छवि में कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि पुलिस की वर्दी से उनके आइकन बने रहने का मार्ग जरूर प्रशस्त रहा। बेदी के पेशेवर काम.काज की एक बड़ी ख्याति ष्क्रेन बेदीष् के रूप में रही हैए जिसके पीछे भी लोगों में खाकी वर्दीधारी एक तेज तर्रार महिला को देखने का अचंभा ही ज्यादा शामिल थाय अन्यथा सड़कों से गाड़ियां उठवाने का यह काम कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर बखूबी निभा सकता है। हांए पुलिस विभाग से बाहर तिहाड़ जेल का स्वतंत्र प्रभार मिलने पर बेदी की नेतृत्व क्षमता को प्रचार उड़ान भरने का मौका मिलाए जिसे उन्होंने भुनाया भी खूब। मेगसैसे पुरस्कारए संयुक्त राष्ट्र में बड़े वेतन पर तैनातीए मोटे अनुदानों पर पलते दो एनजीओए अण्णा का लोकपाल आंदोलन. स्वीकारना होगा कि किरण बेदी की आइकॉनिक छवि को इस चकाचौंध भरी यात्रा में ज्यादा खरोंचें नहीं लगीं। चुनावी दांव पर कुर्बान किए जाने को बेदी की यही छवि है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर उनचास दिन शासन करने वाली पार्टी दिल्ली चुनाव में जनपरस्ती की नई राजनीतिक भाषा न बोल पा रही होती तो भाजपा को मोदीपरस्ती के फलक पर किरण बेदी को उतारने की मजबूरी न होती। यानी केजरीवाल बनाम किरण बेदी के शोर के बावजूद दिल्ली में टक्कर वास्तव में जनपरस्ती बनाम मोदीपरस्ती के बीच है।

गतांक की चीरफ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 16-31 जनवरी 2015 के अंक में अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर लेख पढ़ने को मिले। लेख 'हरसरू भूमि-कांड के शिकार बने गुड़गांव आयुक्त प्रदीप कासनी-दांव पर लगे हों हज़ारों करोड़ तो बड़े पेटों में उठते हैं मरोड़' तथा 'भूमि माता किसकी भारी जेब जिसकी' से भ्रष्टाचार व नौकरशाहों की निष्ठा तथा निडरता से कार्य करने की स्वतंत्रता के प्रति भाजपा सरकार का दोगलापन तथा कथनी व करनी में अंतर स्पष्ट प्रकट होता है।

गौरतलब है कि जब पूर्व मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने प्रदीप कासनी को परेशान किया था तब विपक्षी भाजपा ने हुड्डा की आलोचना की और प्रदीप कासनी की प्रशंसा की। परंतु सत्तारूढ होने पर भाजपा हुड्डा से भी आगे निकल गई। उसने कासनी को गुड़गांव आयुक्त पद से हटा दिया और आश्चर्य है कि अभी तक कासनी की कहीं तैनाती भी नहीं की है जबकि उनका कोई दोष अथवा अपराध भी नहीं है। खट्टर सरकार को डर है कि कासनी को आगे जिस स्थान पर तैनाती की जाएगी तो वह वहां फ़िर किसी कम्पनी के काले कारनामें उज़ागर न कर दे और लेने के देने न पड़ जाए।

'राजनीतिक अखाड़े में दो स्टंटबाज़ -एक और स्टंट: हिंदू महासभा पी के से नाराज' लेख में राजनीति और धर्म के गठजोड़ के कुचक्र का पर्दाफ़ाश किया गया है। अपनी छवि उभारने और भोले-भाले भक्तों में अपनी श्रद्धा की जड़ें मज़बूत करने व अपनी नकारात्मक छवि न उभरे, इसके लिए रामदेव व गुरमीत राम रहीम ने स्टंट करने का सहारा लिया। रामदेव ने दंगल में जाकर कुश्ती का स्टंट किया तो राम रहीम ने 'मैसेंजर ऑफ़ गॉड' फ़िल्म बना डाली जिसमें राम रहीम स्टंट करते दिखाई देते हैं।

गौरतलब है कि हिंदू महासभा अमीर खान की फ़िल्म 'पी के' से नाराज है और उसके कार्य-कर्ता जगह-जगह पर इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु राम रहीम की फ़िल्म का समर्थन करते हैं। क्योंकि राम रहीम ने लोकसभा और हरियाणा विधान सभा चुनावों में भाजपा का खुलकर समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष ने राम रहीम की फ़िल्म को मंजूरी के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा बोर्ड के काम में दखलंदाज़ी का आरोप लगाया है और अध्यक्ष समेत बोर्ड के सदस्यों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है।

लेख 'मुखौटा' काफ़ी रूचिकर लगा। संघ परिवार ने मोदी को विकास पुरुष के रूप में जनता के सामने पेश कर रखा है और मोदी भी विकास की ही बातें करते हैं जबकि संघ परिवार व भाजपा के नेताओं के साम्प्रदायवादी व कट्टरपंथी भाषणों व कृत्यों को नज़रंदाज कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मोदी विकास के नाम पर कट्टरपंथ को ही संरक्षण दे रहे हैं।

'मानव संसाधन विकास मंत्री जी-राष्ट्रपति भवन में आपकी जगह हो न हो इतिहास में आपकी जगह पक्की है' लेख में मंत्री स्मृति इरानी व ज्योतिष पर अच्छा कटाक्ष किया गया है। जब भी केन्द्र में भाजपा नीत एनडीए सरकार बनी है तभी मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा में संघ परिवार के एजेंडा को ही लागू किया है। स्मृति इरानी ने तो प्रत्येक संस्थान में आरएसएस से जुड़े व्यक्यिों की नियुक्ति करनी शुरू कर रखी है तथा संघी दीनानाथ बत्रा के परामर्श से नई शिक्षा नीति भी बनानी प्रारम्भ कर दी है। ज्योतिष तो संघ परिवार का पसंदीदा प्रमुख विषय है जिसको उन्होंने लोकप्रिय बनाना है।

लेख 'पुलिस सुधार की कवायद' के जरिए आसाम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस मुखिया और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के 49 वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की 'स्मार्ट' पुलिस का सटीक विश्लेषण किया गया है। लोकसभा चुनाव में मोदी की विजय के बाद प्रतिक्रियावाद का दौर चल पड़ा है और साम्प्रदायिक ताकतें बेख़ौफ़ होकर देश में साम्प्रदायिक तनाव का माहौल बनाने में उतारू है जबकि विपक्ष अभी पराजय के सदमें से उभरा नहीं है।

ऐसे में लेख 'फ़िलहाल नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नहीं' बिल्कुल उपयुक्त है। स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुर्की' द्वारा भाजपा मॉडल व केजरीवाल मॉडल के मुकाबले के संदर्भ में मोदी द्वारा केजरीवाल को जाकर नक्सलियों में शामिल होने का कहने का उचित विश्लेषण किया गया है। केज़रीवाल का मुकाबला करने में असमर्थ पाकर मोदी व भाजपा ने केजरीवाल की पूर्व सहयोगी किरण बेदी को भाजपा में शामिल करके उसे अपने मुख्य मंत्री के पद की उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है।

मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के पाखंड की लेख 'नेता बेचारे प्रचार के मारे' तथा 'स्वच्छ भारत अभियान: नाम बड़े दर्शन छोटे' द्वारा पोल खोली गई है तथा साफ़-सफ़ाई रखने के लिए उपयुक्त व सार्थक उपाय भी बताए गए हैं।

लेख 'राजकीय महिला कॉलेज में प्रिंसिपल के तबादले का खेल' हरियाणा के शिक्षा विभाग की नालायकी को दर्शाता है। हरियाणा में तबादले के संबंध में एक परंपरा है जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय से भी समर्थित है, इसके तहत सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व किसी का तबादला न किया जाए क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व पेंशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होती है। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार की तबादला नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रशंसनीय व प्रेरणादायक हैं।

प्रो. जुगल किशोर गुप्ता